Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.E.C.-205

भारतीय आर्थिक नीति

(Indian Economic Policy)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Bhavya Gupta*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 450/-

Content

भारतीय आर्थिक नीति
(Indian Economic Policy)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-4

Sample Question Paper–1 (Solved) 1

Sample Question Paper–2 (Solved) 1

Sample Question Paper–3 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

भारतीय आर्थिक विकास : एक विहंगम दृष्टि
(Indian Economic Development: An Overview)

1. भारतीय आर्थिक विकास : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1
   (Indian Economic Development: A Historical Perspective)
2. भारतीय अर्थव्यवस्था की संवद्धि एवं संरचना 13
   (Growth and Structure of the Indian Economy)
3. जनांकिकीय संक्रमण और इसके निहितार्थ 23
   (Demographic Transition and its Implications)
4. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources) 35
5. भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना 48
   (Physical and Social Infrastructure)

विकासपरक कार्यनीतियाँ (Development Strategies)

6. राज्य एवं बाजार : भारतीय संदर्भ (State and Market: Indian Context) 63
7. भारत में आर्थिक सुधार (Economic Reforms in India) 74
8. उत्तर आर्थिक सुधार काल में समष्टि स्तरीय विकास 86
   (Major Developments in Post Economic Reform Period)

मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियां (Monetary and Fiscal Policies)

9. मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति (Inflation and Monetary Policy) 102

10. पूंजी बाजार एवं इसका विनियमन (Capital Market and Its Regulations) 115

11. राजकोषीय नीति एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 130
(Fiscal Policy and Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act)

12. भारत में वित्तीय संघवाद (Financial Federism in India) 146

क्षेत्र विशिष्ट मुद्दे एवं नीतियाँ (Sector Specific Issues and Policies)

13. कृषि : मुद्दे, चिन्ताएं नीति और कार्यक्रम 159
(Agriculture: Issues, Concerns, Policy and Programmatic Initiatives)

14. भारत में बड़े उद्योग : मुद्दे और नीतियाँ 175
(Large Scale Industries in India: Issues and Policy)

15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) : मुद्दे और नीति 187
(Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Issues and Policy)

16. सेवा क्षेत्र-I : संगठित क्षेत्र-मुद्दे और नीतियाँ 197
(Services Sector I: Organised Sector - Issues and Policy)

17. सेवा क्षेत्र-II : अनौपचारिक क्षेत्र : मुद्दे और नीतियाँ 208
(Services Sector II: Informal Sector - Issues and Policy)

बाह्य क्षेत्र तथा व्यापार नीति (External Sector and Trade Policy)

18. व्यापार नीति (Trade Policy) 217

19. विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन (Foreign Trade and Balance of Payment) 227

20. विदेशी पूंजी (Foreign Capital) 238

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतीपूर्ण मुद्दे (Major Issues Confronting Indian Economy)

21. गरीबी, कुपोषण और समावेशी विकास : नीतिगत निहितार्थ 249
(Poverty, Malnutrition and Inclusive Growth: Policy Implications)

22. रोजगार और बेरोजगारी : नीतिगत चुनौतियाँ 258
(Employment and Unemployment: Policy Challenges)

23. भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपाय (Social Security Measures in India) 268

24. भारत में क्षेत्रीय विषमताएँ : नीतिगत निहितार्थ 279
(Regional Disparity in India: Policy Implications)

25. सुशासन के संघटक 290
(Ingredients of Good Governance)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भारतीय आर्थिक नीति
(Indian Economic Policy)

M.E.C.-205

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग में से प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार दीजिए।*

भाग-क

नोट : इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. जनसंख्या लाभांश की अवधारणा और हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था के समक्ष इस मुद्दे से संबंधित उत्पन्न चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए की गई प्रमुख नीतिगत पहलों और सुझावों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-27, 'जनांकिकीय लाभांश की संकल्पना' तथा पृष्ठ-31, प्रश्न-8

प्रश्न 2. भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके समक्ष मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-17, पृष्ठ-209, 'अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि के पीछे कारक' तथा पृष्ठ-210, अनौपचारिक सेवा क्षेत्र : मुद्दे एवं चुनौतियां'

प्रश्न 3. राजकोषीय संघवाद में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन से आप क्या समझते हैं? 14वें और 15वें वित्त आयोग ने इन असंतुलनों को कम करने में कितनी प्रगति की है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-150, 'केन्द्रीकरण एवं लंबवत असंतुलन' तथा 'क्षेत्रीय समता और क्षैतिज असंतुलन' पृष्ठ-148, '14वां और 15वां वित्त आयोग'

प्रश्न 4. भारत के आर्थिक विकास को चलाने में विदेशी पूंजी के विभिन्न रूपों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-20, पृष्ठ-239, 'भारत में विदेशी निवेश', पृष्ठ-240, 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए अहम कदम'

भाग-ख

नोट : इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. ''भारत में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) तेजी से बढ़ रहा है।'' टिप्पणी कीजिए। इसकी वृद्धि के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार हैं? इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-198, 'सेवा क्षेत्र में विकास के कारक', पृष्ठ-203, प्रश्न-6, पृष्ठ-199 'भारत में सेवा क्षेत्र पर विमुद्रीकरण का प्रभाव'

प्रश्न 6. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे महत्त्वपूर्ण मुद्दों का विवरण दीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई औद्योगिक नीति के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-178, 'औद्योगिक क्षेत्र के सम्मुख नाजुक मुद्दे', पृष्ठ-179, 'नई औद्योगिक नीति संबंधी दृष्टिकोण'

प्रश्न 7. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ''हरित क्रांति ने अपनी धार खो दी है और भारत को एक और हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति की जरूरत है''? अपने उत्तर के समर्थन में औचित्य दीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-169, प्रश्न-12

प्रश्न 8. ''बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या गरीबी की सीमा से संबंधित है।'' बताइए कि किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजना इन समस्याओं से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाती है।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-21, पृष्ठ-252, 'कुपोषण एवं गरीबी–एक तुलनात्मक विश्लेषण', 'समावेशी विकास : नीतिगत निहितार्थ'

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

प्रश्न 9. शासन और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सुशासन की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-25, पृष्ठ-290, 'शासन', पृष्ठ-291, 'सुशासन', पृष्ठ-293, प्रश्न-1

प्रश्न 10. भारत में बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए। क्या ये उपाय इस समस्या से निपटने के लिए काफी हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-22, पृष्ठ-265, प्रश्न-8 पृष्ठ-262, 'चिंता के मुद्दे'

इसे भी देखें–नहीं, ये उपाय काफी नहीं हैं।

प्रश्न 11. क्षेत्रीय विषमता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रीय विषमता को हटाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-24, पृष्ठ-279, 'अंत:वैयक्तिक क्षेत्रीय विषमताएं : धारणा और सिद्धांत' तथा पृष्ठ-282, 'क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उपाय'

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) दिवाला एवं दिवालिया कोड

उत्तर–दिवाला वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया कर्ज अदा करने में अक्षम हो जाती है।

दिवालियापन वह ऐसी स्थिति है, जब किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को बकाया कर्ज अदा न कर पाने की स्थिति में, सक्षम न्यायालय द्वारा इसे हल करने और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यह ऋणों को भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा होती है।

(ख) उप-राष्ट्रीय उधार

उत्तर–सरकारें अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने से रोकने के लिए ऑफ बजट बॉरोइंग का सहारा लेती हैं। इसके जरिए सरकार सीधे पैसे ना उठाकर अपनी किसी एजेंसी के जरिए पैसों का इंतजाम करती है और अपने खर्चों को पूरा करती है।

(ग) जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (OFDI)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-20, पृष्ठ-241, 'पूंजी बहिर्वाह'

(घ) औद्योगिक रुग्णता

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-178, 'औद्योगिक रुग्णता'

(ङ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

उत्तर–PPP अर्थात सार्वजनिक-निजी साझेदारी की मदद से सरकार न केवल अपने अति महत्त्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरी गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कर पाती है, बल्कि अपने कीमती बचे हुए समय को अन्य मौलिक कार्यों में लगातार जनता व राष्ट्र का कल्याण भी सुनिश्चित कर पाती है।

■■

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

भारतीय आर्थिक नीति
(Indian Economic Policy)

भारतीय आर्थिक विकास : एक विहंगम दृष्टि
(Indian Economic Development: An Overview)

भारतीय आर्थिक विकास : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
(Indian Economic Development: A Historical Perspective)

1

परिचय

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन देखा गया। ब्रिटिश वर्चस्व ने भारत में आधुनिक कॉर्पोरेट, राजनीतिक, वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग, पारगमन और संचार सभी में सुधार हुआ। संचार और परिवहन उन्नति लाभदायक थी। 1940 के दशक में, भारत में 42,000 मील रेल और 65,000 किमी पक्की सड़कें थीं।

सड़कों और रेलमार्गों ने देश को एकीकृत करने में मदद की, लोगों और सामानों को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत ने डाक और तार प्रणाली की स्थापना की। इससे प्रमुख आर्थिक विकास नहीं हुआ। ये परिवर्तन औपनिवेशिक ढाँचे के अंदर हुए। अंग्रेजों ने सस्ते कच्चे माल के साथ अपने कारखानों की आपूर्ति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। उन्होंने भारत में औद्योगिक सामान बेचने के लिए हाथ से बने उद्योगों को नष्ट कर दिया। कुछ खास तरीकों से, औपनिवेशिक संबंध ने भारतीय आर्थिक प्रगति को भी गति दी और धीमा भी कर दिया।

अध्याय का विहंगावलोकन

अठारहवीं शताब्दी में भारत

अठारहवीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप आधुनिक विश्व का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। भारत की समृद्धि के कारण ही अंग्रेज भारत की ओर आकर्षित हुए। ''भारत ने लंबे समय से सभ्य दुनिया के लिए माने जाने वाले उद्योग या उत्पाद के लगभग हर रूप का उत्पादन किया था। भारत यूरोप या एशिया के किसी भी देश की तुलना में कहीं अधिक उन्नत औद्योगिक और विनिर्माण राष्ट्र था''। उपनिवेशीकरण से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से विश्व पर हावी थी। तालिका-1 को 2001 से 2003 ईस्वी तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख राष्ट्रों के प्रतिशत योगदान की जानकारी के साथ अद्यतन किया गया है।

तालिका 1: विश्व जीडीपी में प्रमुख देशों का अंशभाग 2001-2003 ईस्वी (संकल विश्व का प्रतिशत)

देश	1	1000	1500	1600	1700	1820	1870	1913	1950	1973	2003
12 देश* योगफल	10.6	7.0	15.5	17.1	19.1	20.5	30.5	30.8	24.1	22.8	16.5
योगफल पश्चिमी यूरोप	13.7	9.1	17.8	19.8	21.9	23.0	33.1	33.0	26.2	25.6	19.2
यूएसए	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	1.8	8.9	18.9	27.3	22.1	20.6
चीन	25.4	22.1	24.9	29.0	22.3	32.9	17.1	8.8	4.6	4.6	15.1
भारत	32.0	28.1	24.4	22.4	24.4	16.0	12.1	7.5	4.2	3.1	5.5
अन्य पूर्वी-एशिया	4.6	7.5	8.4	7.4	7.7	5.2	4.8	4.5	4.8	5.2	9.6
विश्व का योगफल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: 'The Contours of World Economy 1-2030 AD by Late British Professor Angus Maddison, Oxford University Press 2007, p.p. 381. नामक पुस्तक की तालिका 1.6 से अपनाया गया है।

**ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके।*

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

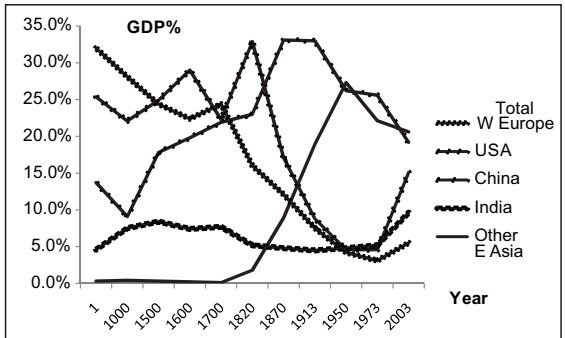

विश्व जीडिपी में प्रमुख देशों के शेयर में रुझान

उपर्युक्त तालिका और आँकड़ों से कुछ निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित है, जो दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में उनके % योगदान के संदर्भ में पिछले 2000 वर्षों में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे बदली हैं–

1. अठारहवीं शताब्दी से पहले वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के अपने प्रतिशत के संदर्भ में, भारत और चीन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ थीं।
2. भारत पहली सहस्राब्दी (यानी, 1 CE से 1000 CE तक) से 14वीं शताब्दी (जहां CE सामान्य युग के लिए खड़ा है) तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पादन का योगदानकर्ता था।
3. भारत ने सामान्य युग की पहली 17 शताब्दियों (1 CE से 1700 CE) के दौरान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (32 और 24.4% के बीच) में सबसे अधिक योगदान दिया है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के अपवाद को छोड़कर, जब वह शताब्दी 1500 के अंत में चीन से लगभग 0.5 प्रतिशत अंक और शताब्दी 1600 के मोड़ पर लगभग 7 प्रतिशत अंक से पिछड़ गया था।
4. 1700 से 1870 तक, भारत का सकल घरेलू उत्पाद योगदान 24.4% से 12% तक, 12 प्रतिशत अंकों से अधिक की कमी के कारण आधे से भी कम हो गया। इसी समय अवधि के दौरान पश्चिमी यूरोप में लगभग 33%, 22% से 33% तक और 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।

ब्रितानी शासन–औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की स्थिति

पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन

भारत की अर्थव्यवस्था एक अधीनस्थ तरीके से अंततः उपनिवेशवाद के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हुई। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, जिसका चरित्र और संरचना ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की माँगों द्वारा परिभाषित की गई थी। अठारहवीं शताब्दी परिवर्तन का समय था। अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उजागर किया गया था। इसके अतिरिक्त, जैसे ही औपनिवेशिक सत्ता ने पकड़ बनाई, किसान निर्यात और बहुराष्ट्रीय निगम के समर्थन के आधार पर एक नई अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रितानी साम्राज्य भारत के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित हुआ, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारत एक महत्त्वपूर्ण बाजार के साथ-साथ भोजन और कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में सेवा प्रदान करता है।

किसान वर्ग का दारिद्रीकरण

सबसे पहले कृषि उद्योग को नुकसान हुआ, 1765 में बंगाल, बिहार और ओडिशा को दीवानी (कराधान अधिकार) देने के बाद थोड़े समय के भीतर ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व को अधिकतम करने की रणनीति के परिणामस्वरूप भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और दीवानी प्रांतों के समाज का सकल विनाश हुआ। 1769-1770 का अकाल, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल की लगभग एक-तिहाई आबादी समाप्त हो गई और जिसने उस समय प्रचलित सामान्य उथल-पुथल और गरीबी की चेतावनी के रूप में कार्य किया, इस स्थिति का एक संकेत था।

कंपनी ने पहले से मौजूद भूधृति प्रणाली को बदल दिया और तीन नई व्यवस्थाएँ स्थापित कीं–दक्षिणी और पश्चिमी भारत में रैयतवारी, पश्चिमी गंगा के मैदानों में महलवारी और पूर्वी भारत में जमींदारी। इसका लक्ष्य संपत्ति पर उच्चतम निश्चित लाभ हासिल करते हुए किसानों की भलाई की रक्षा करना था। जमींदारी प्रणाली के साथ, जिसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, जमींदारी को संपत्ति के अधिकार और संपूर्ण समय के लिए एक निश्चित आय प्राप्त हुई।

कृषि का व्यावसायीकरण

पूंजीवादी कृषि की ओर एक कदम कृषि का व्यावसायीकरण है। व्यावसायीकरण और काश्तकारी कानूनों के कारण कई स्थानों पर धनी किसानों का एक वर्ग उभरकर सामने आया, लेकिन उनमें से अधिकांश ने भूमि का अधिग्रहण करने और जमींदार बनने या धन उधार देने का फैसला किया।

कृषि मजदूर

गरीब किसान, जिनमें से अधिकांश छोटे किसान, इच्छा पर किरायेदार (अस्थाई मुजारे) और बटाईदार थे, के पास बेहतर जानवरों और बीजों, अधिक खाद और उर्वरकों और बेहतर उत्पादन विधियों के उपयोग के माध्यम से कृषि की उन्नति में संलग्न होने के लिए वित्त और प्रेरणा की कमी थी। भूमिहीन किसानों, दिवालिया कारीगरों और हस्तशिल्पियों को वि-औद्योगीकरण और आधुनिक उद्योग की कमी के कारण भूमि के नुकसान और भीड़ के कारण साहूकारों और जमींदारों के किरायेदार बनने के लिए मजबूर किया गया था।

आधुनिकीकरण का अभाव

भारतीय कृषि में मुश्किल से ही अन्य राष्ट्रों के आधुनिकीकृत और परिष्कृत तकनीकी का समावेश किया गया। 'द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' 1857-1947 (ओयूपी, 2011, पृष्ठ 110) में तीर्थंकर रॉय लिखते हैं, ''ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि उपकरणों के मूल सेट में थोड़ा बदलाव आया।'' भारतीय ग्रामीण अभी भी अपने प्राचीन, आदिम उपकरणों का उपयोग करते थे। 1951 में, 31.3 मिलियन लकड़ी के हल बनाम 0.93 मिलियन लोहे के हल थे। गाय का गोबर, मल और मवेशियों की हड्डियाँ बरबाद हो गईं, लेकिन अकार्बनिक उर्वरक दुर्लभ थे। 1938-1939 में, केवल 11% कृषि भूमि में उन्नत बीजों का उपयोग किया गया था, वह भी ज्यादातर गैर-खाद्य फसलों के लिए। कृषि को नजरअंदाज कर दिया गया था। 1946 में 9 कृषि महाविद्यालय थे। बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के विलवण ीकरण को बहुत कम धन मिला। सिर्फ सिंचाई सुधरी थी।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

कारीगरों और हस्तशिल्पों की बर्बादी

18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, भारत यूरोप में वस्त्रों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता था और सभी निर्मित वस्तुओं का एक चौथाई योगदान देता था। ब्रिटिश विजय ने विनिर्माण और कृषि के बीच पारंपरिक भारतीय संबंधों को तोड़ दिया। गाँवों की स्वायत्तता खत्म हो गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने बंगाली कारीगरों को अपना माल बाजार मूल्य से कम पर बेचने और उनकी सेवाओं के लिए कम भुगतान करने के लिए मजबूर किया। कई ने अपने पूर्वजों के व्यापार को खो दिया।

औद्योगिक क्रांति के बाद, शहरी हस्तशिल्प क्षेत्र, जिसने भारत को यूरोपीय बाजारों में उत्कृष्टता का पर्याय बना दिया था, धराशायी हो गया। औपनिवेशिक नियंत्रण ने निर्यात माँग को कम करते हुए, ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी। 1813 के बाद, अंग्रेजों ने भारत पर एक तरफा मुक्त व्यापार नियम लागू किया और सूती वस्त्रों ने तेजी से आक्रमण किया। पुरातन भारतीय माल भाप से चलने वाले बड़े पैमाने पर उत्पादित सामानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे ज्यादा नुकसान कपास की बुनाई और कताई को हुआ। रेशम और ऊनी वस्त्र, तेल निकालने, चमड़ा, रंगाई, लोहा, चीनी मिट्टी की चीजें, धातु और शिपिंग को भी नुकसान उठाना पड़ा।

आधुनिक उद्योगों की स्थिति

1850 और 1914 के बीच, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जूट उद्योग, चौथा या पाँचवां सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग और तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क था। आधुनिक औद्योगिक तकनीकों का प्रसार धीमा था। स्वतंत्रता के समय भारत गरीब और गैर-औद्योगिक था। जैसे ही यूरोप का औद्योगीकरण हुआ, भारत का पुनऔंद्योगीकरण हुआ। नकदी, बाजार, कुशल श्रम और विस्तार के लिए उद्यमशीलता की भावना होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ठप हो गई।

1850 के दशक में भारत में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खनन उद्योगों ने मशीन युग की शुरुआत की। कावसजी नानाभॉय ने 1853 में बॉम्बे की पहली कपड़ा फैक्ट्री और 1855 में बंगाल की पहली जूट मिल की स्थापना की। ये उद्योग धीरे-धीरे पनपे। 1900 की शुरुआत में, भारत में 206 सूती मिलें थीं, जिनमें 1,96,000 व्यक्ति कार्यरत थे। 1901 में, 36 जूट मिलों में लगभग 1,15,000 व्यक्ति कार्यरत थे।

1906 में कोयले की खानों में लगभग 100,000 लोगों ने काम किया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कॉटन जिन्स और प्रेस, चावल, गेहूं और लकड़ी की मिलें, चमड़े के टेनरियों, ऊनी वस्त्र, चीनी मिलों, लोहा और इस्पात के काम, और नमक, अभ्रक और शोरा सहित खनिज उद्योगों का विकास हुआ। 1930 के दशक में सीमेंट, कागज, माचिस, चीनी और कांच का विकास हुआ। ये उद्योग धीरे-धीरे विकसित हुए।

धन का निकास (बहना) (Drain of Wealth)

ब्रिटेन को भारत का धन प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक राज्य, प्रशासक और व्यापारी सामाजिक अधिशेष और निवेश योग्य पूंजी को ब्रिटेन ले गए। यह रुपये के बदले में भारतीय कमोडिटी खरीदारों को लंदन में 'काउंसिल बिल' बेचकर किया गया था।

1757 के बाद आर्थिक बहिर्वाह शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वर्ष बंगाल को बुलियन का निर्यात बंद कर दिया, जबकि कुछ अभी भी कहीं और यात्रा कर रहे थे। बंगाल के प्रादेशिक राजस्व अधिशेष ने इसके अपने और भारत के सभी अधिग्रहणों को वित्त पोषित किया। इस पैसे को 'निवेश' के रूप में जाना जाता था।

मोंटगोमरी मार्टिन ने 1806-1816 में बंगाल और बिहार में आर्थिक निकास की पहचान की। ''ब्रिटिश भारत पर वार्षिक निकासी, £3,000,000 के 12% (सामान्य भारतीय दर) चक्रवृद्धि ब्याज पर, £723,000,000 स्टर्लिंग तक जमा हो गई है,'' उन्होंने टिप्पणी की कि इंग्लैंड में भी, एक स्थिर नाली उसे दरिद्र बना देगी। लगभग एक शताब्दी बाद विलियम डिग्बी आर्थिक निकासी के बारे में भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। विलियम डिग्बी ने निकासी का अनुमान £60,080,000,000 लगाया।

यह धन निकासी बहुआयामी थी। इनमें सैन्य खर्च, ईस्ट इंडिया कंपनी के विदेशी ऋण पर ब्याज, सड़कों, सिंचाई और रेलवे में विदेशी निवेश पर वापसी की गारंटी और 'घरेलू शुल्क' शामिल थे, जिसमें लंदन में भारत कार्यालय के लिए भुगतान और नागरिक और सैन्य वेतन और पेंशन शामिल थे।

गरीबी और अकाल

औपनिवेशिक अल्पविकास ने किसानों और शिल्पकार को तबाह कर दिया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, स्वदेशी उद्योगों की गिरावट, उन्हें बदलने के लिए आधुनिक उद्योगों की विफलता, उच्च कर, ब्रिटेन में धन का प्रवाह, और एक प्रतिगामी कृषि संरचना के कारण, भारतीय अत्यधिक गरीबी में रहते थे। जमींदार और साहूकार गरीब किसानों का शोषण करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकाल ने भारत में गरीबी और पीड़ा को प्रभावित किया। ब्रिटिश युग के दौरान, कई क्षेत्रों ने बार-बार अभाव और अकाल का अनुभव किया। 1770 में, बंगाल में भुखमरी ने एक- तिहाई आबादी को मार डाला। 1865-1866 में एक अकाल ने बंगाल, बिहार, मद्रास और ओडिशा में लगभग बीस लाख लोगों की जान ले ली। 1876-1878 में, 40 लाख लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश बंबई और मद्रास में थे। 1897-1898 में 50 लाख मौतें हुईं। स्थानीय अकाल और कमी भी बहुतायत में देखे गए।

समष्टि आर्थिक नीति

ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न स्तरों और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के निम्न स्तरों, एक स्थिर कृषि क्षेत्र, स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योग की घटती हिस्सेदारी, पूंजीगत सामान उद्योग के लिए एक कमजोर आधार, ब्रिटेन की आपूर्ति पर केंद्रित विदेशी व्यापार, औद्योगिक क्रांति, व्यापक गरीबी और बेरोजगारी की व्यापकता, और अन्य मुद्दों से त्रस्त थी। निम्नलिखित व्यापक आर्थिक संकेतकों का उपयोग अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए किया जा सकता है।

बचत और निवेश

पूंजी संचय की प्रक्रिया, जो निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पन्न आर्थिक अधिशेष या बचत की राशि और उपयोग का एक कार्य है, यह निर्धारित करती है कि एक अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो जाएगी। 1914 से 1946 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था की शुद्ध बचत उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.75 प्रतिशत थी।

इस राशि की तुलना 1971 से 1975 तक की शुद्ध बचत से की जा सकती है, जो कि GNP का 12% थी और हाल ही में, 2017 से 2018 तक की सकल बचत, जो GDP का 30% थी। 1914-1946

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

के वर्षों में, कुल पूंजी निर्माण का प्रतिशत जीएनपी का 6.75% था, जबकि 1971–1975 के वर्षों में 20.14 प्रतिशत और 2017–18 के वर्षों में 32.3% था। इसके अतिरिक्त, उद्योग ने 1914 और 1946 के बीच GNP का केवल 1.78 प्रतिशत बनाने वाली मशीनरी के साथ पूंजी संचय के इस निम्न स्तर में बहुत कम योगदान दिया। 1971–1975 में, यह राशि GNP का 6.53 प्रतिशत थी।

राजकोषीय नीति

देश को नियंत्रित करने के लिए औपनिवेशिक ढाँचे के विभिन्न पहलुओं को बनाने, चुनने और बनाए रखने में राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका भारत के शासन की एक विशेषता थी। ब्रिटेन में भारत की कार्रवाइयों को तय करते समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार, उद्योग और कृषि के लिए राज्य के समर्थन की कमी भारत की अविकसितता का एक महत्त्वपूर्ण कारक था। भारत में औपनिवेशिक सत्ता को सहारा देने वाली रणनीति के अन्य तत्वों में शामिल हैं–

***(i)* प्रतिगामी कर संरचना**–भारतीय कर प्रणाली अविश्वसनीय रूप से अनुचित थी। उच्च-आय वर्ग, जिसमें अत्यधिक भुगतान वाले नौकरशाह, जमींदार, व्यापारी और व्यापारी शामिल थे, ने पूरे औपनिवेशिक काल में मुश्किल से कोई कर चुकाया, जबकि गरीब और किसान क्रमशः पर्याप्त भू-राजस्व और नमक कर का भुगतान करने के बोझ तले दबे हुए थे। प्रत्यक्ष कर बिल्कुल भी उच्च नहीं थे। 1946–1947 में 3,60,000 लोगों ने आयकर का भुगतान किया।

***(ii)* सैन्य खर्च**–सैन्य व्यय और नागरिक प्रशासन, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कर संग्रह पर केंद्रित था, ने सार्वजनिक राजस्व का अधिकांश हिस्सा ले लिया। 1890 के बाद, केंद्र सरकार का राजस्व लगभग पूरी तरह से सैन्य खर्च में चला गया। 1947–1948 में यह प्रतिशत लगभग 47% था।

***(iii)* कृषि, उद्योग और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास पर अल्प व्यय**–जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, औपनिवेशिक राज्य ने भारत के सामाजिक अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा विनियोजित किया। हालांकि इसने कृषि, उद्योग, सामाजिक बुनियादी ढाँचे या सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे राष्ट्र निर्माण की पहल पर इसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च किया।

व्यापार नीति

व्यापार नीति में दो शताब्दियों (1757–1947) में महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन देखे गए। चार अलग-अलग समय अवधियों की पहचान की जा सकती है–1759–1813, 1813–1850, 1850–1914 और 1914–1947।

***(i)* 1759–1813**–पहले युग को वाणिज्यवाद के युग के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और ब्रिटेन के बीच एकाधिकार व्यापार को लागू करने का प्रयास किया और इस दौरान अपना राजनीतिक प्रभुत्व हासिल किया। फिर भी, व्यक्तिगत व्यापारियों के कार्यों के कारण, निगम अनिवार्य रूप से विफल था। व्यापार के महत्त्वपूर्ण पहलू यह थे कि यह स्थापित चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा और यह कीमती धातुओं और विशिष्ट तैयार माल के लिए उच्च अंत वस्त्रों, खाद्य पदार्थों का, अन्य कच्चे माल के आदान-प्रदान से बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अपने भारतीय उपनिवेशों के बजटीय स्रोतों के अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

***(ii)* 1813–1850**–इस समय के दौरान भारतीय व्यापार के कमोडिटी मिश्रण में एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन आया, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक बना रहा। भारत प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति करता में निर्माण और उत्पादों की निर्यातक के बजाय तैयार उपभोक्ता वस्तुओं और मध्यवर्ती औद्योगिक सामानों का आयातक बन गया था। 1811–12 में कलकत्ता के कुल निर्यात मूल्यों का 33 प्रतिशत, 1814–15 में 14.3 प्रतिशत और 1839–40 में केवल 5 प्रतिशत हिस्सा था। 1814 और 1850 के बीच की अवधि के दौरान नील (इंडिगो), कच्चा रेशम, अफीम और कपास चार मुख्य निर्यात थे।

***(iii)* 1850–1914**–क्रीमिया युद्ध की शुरुआत और 1850 के दशक के दौरान भारत में रेलवे लाइनों के निर्माण ने उप-महाद्वीपीय वाणिज्य को एक नया बढ़ावा दिया। अमेरिकी गृहयुद्ध और स्वेज नहर के खुलने के कारण, आने वाले दो दशकों में विदेशी व्यापार की मात्रा और मूल्य आसमान छू गया।

***(iv)* 1914–1947**–1914 में, राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार की अवधि और स्वर्ण मानक विनिमय प्रणाली अचानक समाप्त हो गई। युद्ध के बाद के युग में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य वैश्विक औद्योगिक पुनर्गठन, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के विस्तार, टैरिफ संरक्षण रणनीति और विनिमय दर विनियम जैसे कारकों से विवश था। इसके अलावा, भारत को बुनियादी वस्तुओं के अन्य निर्यातकों के साथ 1929 की महामंदी का सामना करना पड़ा। ये परिवर्तनों युद्ध के बीच की अवधि के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के समग्र प्रक्षेपवक्र में महत्त्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का कारण बने। द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत से लेकर 1946 तक युद्धकालीन प्रतिबंधों और 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल से व्यापार प्रवाह पिछले सात वर्षों में प्रभावित हुआ था।

स्वतंत्र भारत के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लोकप्रिय लोगों का आंदोलन आंदोलन था, जिसने कई भारतीय वर्गों और तबकों का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाली एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का एक साझा लक्ष्य था। भाषणों में, कागजों में, कार्यक्रमों और कार्यों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं और व्यापारिक नेताओं ने नियोजित औद्योगीकरण, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश, कृषि सुधार और एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का आह्वान किया।

एम.जी. रानाडे ने कहा कि कारखाने, स्कूलों और विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक कुशलता से 'राष्ट्र की गतिविधियों का पुनर्जन्म' कर सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मानना था कि उद्योग भारत की विषम आबादी को एकजुट कर सकता है।

'बंगाली' दैनिक ने 18 जनवरी, 1902 को रिपोर्ट किया– ''राजनीतिक अधिकार भारत की विभिन्न जनजातियों को संक्षिप्त रूप से एकजुट कर सकते हैं। एक बार ये अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद, हितों का साझापन ध्वस्त हो सकता है, लेकिन कई भारतीय जातियों का व्यावसायिक संघ बना रहेगा।''

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद, जब श्रमिक और किसान राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मार्च 1931 में अपने कराची अधिवेशन में श्रमिक और किसान हितों का समर्थन किया। कराची के मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव इसे प्रसिद्ध बनाते हैं।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com